>

Title: Need to ban future trading in essential food commodities in the country.

**श्री सज्जन वर्मा (देवास):** कृषि से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संबंध में समय-समय पर अपनी सिफारिशें देने वाली संसदीय स्थाई समिति ने जुलाई, 2008 को अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखते हुए यह उल्लेख किया था कि कृषि उत्पादनों की कीमतों में कृत्रिम बढ़ोत्तरी के लिए देश का वायदा कारोबार जिम्मेदार है। किसानों को इस वायदे सौदे की तकनीकी जानकारी नहीं होने से इसका लाभ बिचौलिए ले जाते हैं और इन्हीं बिचौलियों की वजह से देश में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बनावटी उछाल आता रहता है।

केन्द्र सरकार द्वारा गठित उपभोक्ता मामलों के कार्य समूह ने सर्वानुमति से इसी तरह की रिपोर्ट में अपना अभिमत प्रस्तुत किया है कि आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, दलहन, खाद्य तेल, चावल और चीनी, चना, सोयाबीन, कपास, काली मिर्च, हल्दी, जीरा, सरसों, हरी इलायची आदि में वायदा कारोबार की अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जबसे वायदा कारोबारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं को इस कारोबार से जोड़ा गया है तब से देश में मंहगाई का प्रतिशत बढ़ा है।